Allocation of Funds for Road Safety in North-Eastern Region

1838. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) the details of funds allocated for road safety in the North-Eastern Region for 1996-97, 1997-98 and 1998-99 State-wise;

(b) whether there is a proposal to establish a fund for the development and upkeep of all National Highways in the North-Eastern Region; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) Under National Highway Patrolling Scheme the following funds have been released to the States in the North-Eastern Region:—

(Rs. in Lakhs)

STATES	1996-97	1997-98	1998-99
Assam	25.00	—	—
Mizoram	25.00	—	—
Nagaland	—	25.00	—
Tripura	—	25.00	—
Arunachal Pradesh	—	—	25.00
Meghalaya	—	—	25.00
Manipur	—	—	25.00

(b)and (c) A Non lapsable Central Pool of Resources has been created during 1998-99 with a token provision of Rs. 1.00 crore for funding the specific projects in the North-Eastern States and Sikkim to be identified in consultation with the State Governments and North Eastern Council (NEC). The Central Pool is comprised of contributions by the concerned Central Ministries/ Departments out of the unspent amount from 10% of their Budget earmarked for the North East and Sikkim. The funds being credited by concerned Union Ministries/Departments to the Pool are expected to enable meeting the initial requirement for assisting identified development projects during the current financial year. Project proposals relating, *inter-alia*, to PM's package, recommended by Shukla commission etc. are envisaged to be identified, from time to time, for consideration for assistance from the Central Pool for implementation through appropriate Central/State agencies. However, at present no National Highway project is being funded from the said pool.

उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित किया जाना

1839. श्री राजनाथ सिंह: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति उनके खराब रख-रखाव के कारण बेहद खराब हो गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उनके बेहतर रख-रखाव के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की हुतगामी राजमार्गों में बदलने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) जी नहीं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को, उपलब्ध संसाधनों के भीतर यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

(ग) और (घ) जी हां। राज्यीय राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:—

	प्रस्ताव	लम्बाई (कि०मी०)
1.	दिल्ली-अलीगढ़-ईटा-कानपुर	405
2.	कानपुर-हमीरपुर-महोबा-सागर	180
3.	झांसी-बान्दा-इलाहाबाद-मिर्जापुर	467

	प्रस्ताव	लम्बाई (कि०मी०)
4.	लखनऊ के चारों और रिंग रोड़	80
5.	सहारनपुर-यमुनानगर-पंचकुला	30
6.	अम्बाला-पोन्टा-हरिद्वार	100
7.	बरेली-पीलीभीत-लखीमपुर बस्ती (असम सड़क तक)	—
8.	दिल्ली-बदरीनाथ-केदारनाथ-उत्तरकाशी-हरिद्वार	—

नौवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग को एक्सप्रैस राजमार्ग में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पत्तनों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए योजना

1840. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा देश के पत्तनों/बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए किए गए वित्तीय प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे प्रत्येक बंदरगाह के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई अथवा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त आधुनिकीकरण कार्यक्रम में मुंजा, नांगरोल, पोरबंदर और वेरावल बंदरगाहों को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में आरंभ किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० देवेन्द्र प्रधान): (क) और (ख) 1998-99 के दौरान, देश में महापत्तनों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 726 करोड़ रु० का परिव्यय अनुमोदित किया गया है और इसमें से 340 करोड़ रु० की राशि अक्तूबर, 1998 के अन्त तक खर्च की जा चुकी है तथा शेष परिव्यय वित्त वर्ष की बाकी बची अवधि के दौरान उपयोग में लाए जाने की संभावना है। परिव्यय और खर्च की गई राशि के पत्तनवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	पत्तन का नाम	वार्षिक योजना 1998-99	अक्तूबर, 1998 तक वास्तविक व्यय
1.	कलकत्ता/हल्दिया	30.00	21.19
2.	मुम्बई	110.00	7.90
3.	ज०ला० नेहरू	70.50	5.74
4.	चेन्नई	170.00	129.16
5.	कोचीन	10.00	4.42
6.	विज़ाग	50.00	16.68
7.	कांडला	65.50	18.62
8.	मुरगांव	15.00	14.56
9.	पारादीप	120.50	107.79
10.	नव मंगलूर	30.00	8.12
11.	टूटीकोरिन	55.00	5.38
	जोड़:	726.00	339.56

(ग) जी, नहीं। प्रश्नगत पत्तन लघु पत्तन हैं और उनके विकास और आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी गुजरात सरकार की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Conversion of Pathankot-Mandi Highway into National Highway

1841. SHRIMATI CHANDRESH KUMARI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether State Highway from Pathankot to Mandi district *via* Kangra Sub-Division in Himachal Pradesh has been converted into National Highway;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether some renovation/widening programme of this N.H. has been undertaken; and